

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 155/2022

उम्मेद सिंह पुत्र श्री रेवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी पौख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

— आवेदक

बनाम

गजेन्द्र सिंह हाल तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।

— अनावेदक

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री अरविन्द सैनी, अभिभाषक- आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- अनावेदक की ओर से उपस्थित।

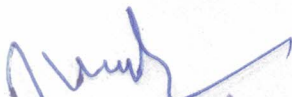
आदेश

दिनांक 20.07.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित सेवामें पेश है कि निम्न वर्णित प्रकरण न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष विचाराधीन है:-

न्यायालय :- तहसीलदार उदयपुरवाटी  
मुकदमा उनवानी :- सरकार बनाम उम्मेद सिंह  
मुकदमा नम्बर :- 11/2021  
किस्म मुकदमा :- 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
तारीख पेशी :- 11/05/2022

विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अन्तिम निर्णय पारित होने के बाद कुर्की अथवा निलामी बाबत आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित प्रकरण में दिनांक 08.04.2022 को पत्रावली वास्ते जबाब में नियत थी लेकिन उक्त प्रकरण में किसी तरह का कोई आदेश पारित किये बिना न्यायालय तहसीलदार द्वारा एक आदेश उक्त भूमि को कुर्क तथा निलाम करने बाबत पारित किया गया है जिसका कोई अधिकार न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी को नहीं था तथा उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का अथवा गिरदावर हल्का ने मौके पर नहीं जाकर अपने कार्यालय में बैठकर दिनांक 21.04.2022 से पूर्व एक रिपोर्ट बाबत कुर्की व निलामी पेश कर दी। प्रार्थी को उक्त निलामी अथवा कुर्की की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थी के मातहत पटवारी हल्का ने धमकी दी कि जल्दी ही प्रार्थी को सुनवाई का कोई मौका नहीं देकर गलत रूप से प्रार्थी के रहवासी मकानात को तोडा जायेगा, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 29.04.2022 को तहसील कार्यालय में आकर नकल हेतु आवेदन करके दिनांक 02.05.2022 को नकलें प्राप्त की तो पता चला कि प्रकरण में गलत रूप से दिनांक 08.04.2022 को कुर्की व निलामी बाबत आदेश पारित किया गया है, जिस पर दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार में आकर रीडर से कार्यवाही को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तो उन्होने प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी को

  
जिला कलक्टर झुंझुनू

धमकी दी कि उन्हे पीठासीन अधिकारी की तरफ से निर्देश है कि आगे जल्दी ही प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के विपरीत करेगा तथा गलत रूप से प्रार्थी के रहवासी मकानात को तोड़ेगा तथा इसके आगे प्रार्थी को कोई जानकारी प्रार्थी को नही दे रहा है, जिससे पीठासीन अधिकारी पर प्रथम दृष्टया रूप से शीघ्र प्रार्थी के विपरीत निर्णय करने के लिए राजनैतिक दबाव साबित है। दिनांक 28.04.2022 को प्रार्थी को अप्रार्थी के मातहत पटवारी हल्का ने ग्राम में धमकी दी है कि उन पर राजनैतिक दबाव है तथा राजनैतिक दबाव के तहत पीठासीन अधिकारी/अप्रार्थी इस प्रकरण का फैसला बिना प्रार्थी को सुने उनके विपरीत करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है, पीठासीन अधिकारी का रवैया साफ जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में राजनैतिक प्रभाव में आकर प्रार्थी के विरुद्ध फैसला करेगे, अगर उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध फैसला होता है तो वह कानून के खिलाफ होगा तथा आवेदक के हक हकुक प्रभावित होंगे, आवेदक को निष्पक्ष न्याय का कानूनी अधिकार प्राप्त है, उक्त प्रकरण को पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव के तहत प्रार्थी के विरुद्ध फैसला देगा, इस कारण उक्त प्रकरण को अन्य निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायालय के अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष लम्बित मुकदमा उनवानी सरकार बनाम उम्मेद सिंह मुकदमा नम्बर 11/2021 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्रांक 355 दिनांक 11.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी ने ग्राम पौख के ख0न0 1702 रकबा 16.93 है0 किस्म गै0मु0 पहाड के 0.20 है0 भूमि पर पक्का मकान व फसल काश्त करके व अतिक्रमण किया हुआ था जिसके विरुद्ध पटवारी हल्का पौख ने दिनांक 05.08.2021 को अतिक्रमी श्री उम्मेद सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी पौख के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी मे मुकदमा नं0 11/2021 दर्ज कर अतिक्रमी के खिलाफ 07.09.2021 को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी उम्मेद सिंह पुत्र रेवन्त सिंह जाति राजपूत के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा 07.09.2021 को तारीख पेश नोटिस अतिक्रमी को तामिल हेतु जारी किया गया। मौके पर प्रार्थी ने उक्त रकबे के आंशिक भाग पर 11-12 मकानों की हवेली तथा शेष भाग पर फसल काश्त की हुई है। उक्त मकानों मे प्रार्थी निवासरत है। प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी व राजनैतिक दबाव नही दिया गया है तथा अतिक्रमित भूमि की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है तथा आगामी तारीख पेशी 12.07.2022 जैराकार है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अन्तिम निर्णय पारित होने के बाद कुर्की अथवा निलामी बाबत आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित प्रकरण में दिनांक 08.04.2022 को पत्रावली वास्ते जबाब में नियत थी लेकिन उक्त प्रकरण में किसी तरह का कोई आदेश पारित किये बिना न्यायालय तहसीलदार द्वारा एक आदेश उक्त भूमि को कुर्क तथा निलाम करने बाबत पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का अथवा गिरदावर हल्का ने मौके पर नही जाकर अपने कार्यालय में बैठकर दिनांक 21.04.2022 से पूर्व एक रिपोर्ट बाबत कुर्की व निलामी पेश कर दी। प्रार्थी को उक्त निलामी अथवा कुर्की की कोई जानकारी नही थी लेकिन दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थी के मातहत पटवारी हल्का ने धमकी दी कि जल्दी ही प्रार्थी को सुनवाई का कोई मौका नही देकर गलत रूप से प्रार्थी के रहवासी मकानात को तोडा जायेगा। पीठासीन अधिकारी पर प्रथम दृष्टया रूप से शीघ्र प्रार्थी के विपरीत निर्णय करने के लिए राजनैतिक दबाव साबित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष लम्बित मुकदमा उनवानी सरकार बनाम उम्मेद

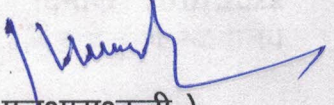
  
जिला कलेक्टर झुन्झुनू

सिंह मुकदमा नम्बर 11/2021 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किया जाना प्रार्थनीय है।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुआ भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 11/2021 उनवानी सरकार बनाम उम्मेद सिंह किस्म मुकदमा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से तहसीलदार गुढागौडजी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी मुकदमा संख्या 11/2021 उनवानी सरकार बनाम उम्मेद सिंह किस्म मुकदमा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को न्यायालय तहसीलदार गुढागौडजी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु तहसीलदार गुढागौडजी के न्यायालय में दिनांक 10.08.2022 को उपस्थित हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल0एस0कुडी )  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं  
जिला कलक्टर झुंझुनूं